GOVT. DEGREE COLLEGE BHOJPUR MORADABAD

Name, **Madhu Tyagi**, Art Professor History

E.Mail, madhutyagi881@gmail.com

Stream, Arts

Name of Course, B.A. III

Name of Sub, History Paper I, History of Modern India

Name of Topic, Political Condition of India in 18th Century, अवध, बंगाल, हैदराबाद

Meta-data- Political Condition of India in 18th Century

Type, PDF Text

घोषणा

यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित प्रसारित या साझा नहीं करेंगे ओर इसका व्यक्तित्व ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे। इस ई–कन्टेन्ट में जो जानकारी दी गयी है। वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है।

Political Condition of India in the 18th Century

मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के समय अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँच गया था, परन्तु 1707 में उसकी मृत्यु के बाद ही शक्तिशाली एवं वैभवशाली साम्राज्य का विघटन तेजी से होना शुरू हो गया। लगभग 50 वर्ष की छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुगल शासक गद्दी पर बैठे परन्तु कोई भी शक्तिशाली और प्रभावशाली शासन न दे पाये। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य के क्षितिज होने से राजनैतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस कारण मुगलों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियन्त्रण वाले प्रान्तों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने के कारण महत्वाकांक्षी सूबेदारों और सरदारों में अपने अर्द्धस्वतन्त्र अथवा स्वतन्त्र राज्य बनाने की होड़ शुरू हो गयी। इस समय उदित होने वाले राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. मुगल साम्राज्य से अपने को अलग करके बने स्वतन्त्र राज्य– अवध, बंगाल और हैदराबाद।
2. मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर स्थापित नये राज्य– मराठा, पंजाब, जाट राज्य।
3. स्वतन्त्र राज्य– मैसूर, राजपूत राज्य, केरल

अवध, हैदराबाद और बंगाल ये तीनों राज्य के प्रांतीय गवर्नर मुगलों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से मुगल प्रशासन के नियन्त्रण में थे तथा बाद में इन राज्यों ने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। ये राज्य दिल्ली से कई चरणों में अलग हुए। इन राज्यों ने मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता को चुनौती नहीं दी पर इनके गवर्नरों ने व्यावहारिक तौर पर स्वतन्त्र और वंशानुगत सत्ता की स्थापना की और उस क्षेत्र में सभी पद और अधिकारी उसके नियन्त्रण में आ गये। इन राज्यों के द्वारा स्वायत्त राजनैतिक शक्तियों के उदय की ही अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार वृहद, मुगल संस्थागत ढाँचे के तहत एक नई राजनैतिक व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ।

अवध– अवध के स्वतन्त्र राज्य का संस्थापक सादत खाँ अथवा बुरहानलमुल्क था। उसने सैय्यद बन्धुओं के विरूद्ध षड़यन्त्र में भाग लिया जिसके फलस्वरूप उसे क्रमशः पंचहजारी, सप्तहजारी का मनसव मिला साथ ही बुरहानुलमुल्क की उपाधी भी। 1722 में मुगल बादशाह द्वारा सादत खाँ को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। परन्तु उसने इसके बाद अवध को एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया। अवध के सूबेदार के रूप में उसे कई समस्याओं जैसे स्थानीय सरदारों और राजाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। साथ ही उन जमींदारों जिन्होंने न केवल भू–राजस्व देना बन्द कर दिया बल्कि अपनी सेनाओं तथा किलों के द्वारा स्वतन्त्र सरदारों की भाँति कार्य करने लगे। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए स्थानीय जमींदारों के विद्रोहों को दबाना, मदद–ए–माश पाने वालों की शक्ति और अधिकारों में कमी करना, राजस्व वसूली को नियमित करना था। उसने स्थानीय पदाधिकारियों को नियुक्त करते समय उनकी व्यक्तिगत वफादारी को भी ध्यान में रखा।

1739 में सादत खाँ को नादिरशाह के विरूद्ध लड़ने के लिये दिल्ली बुलाया गया। वीरतापूर्वक लड़ते हुए उसे बन्दी बना लिया गया। उसने नादिरशाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया साथ ही 20 करोड़ रूपये की आशा दिलाई और जब यह धन माँगा गया तो सादत ने विष खाकर आत्महत्या कर ली।

सादत खाँ के बाद उसका दामाद सफदरजंग उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 ई० में सम्राट मुहम्मदशाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया और

उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। उसने पहले की नीति का अनुसरण करते हुए जमींदारों के साथ कठोरता का व्यवहार किया परन्तु पेशवा के साथ समझौता करने के अपने प्रयास में वह असफल रहा।

बंगाल– 1700 ई० में मुर्शीद कुली खाँ को औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान बनाया गया और बाद में राजस्व प्रशासन में उसकी सफलता और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फैली अनिश्चितता के कारण उसे बंगाल की सूबेदारी 1717 ई० में प्राप्त हो गयी। फरूखसियर ने बाद में उड़ीसा की सूबेदारी भी सौंप दी। मुर्शीद खाँ ने दीवान और नाजिम का पद मिलाकर एक कर दिया और राजस्व सुधार के लिए उसने जमींदार जो बिचौलियों के रूप में थे, उनका खात्मा कर विद्रोही जमींदारों का उड़ीसा के सीमान्त प्रान्तों में निष्कासन कर दिया। राजस्व वसूल करने और भुगतान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाले बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन के साथ खालसा भूमि का विस्तार किया। इन सभी कार्यों से बंगाल में व्यापार और वाणिज्य में बहुत उन्नति हुई। मुर्शीद कुली ने मुगलों से अपने औपचारिक सम्बन्ध कभी नहीं तोड़े और बंगाल का वार्षिक राजस्व नियमित रूप से दिल्ली भेजते रहे। उसने अपने नाती सरफराज को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके बंगाल में वंशानुगत शासन की परम्परा की शुरूआत की।

1727 में सरफराज को उसके पिता शुजाउद्दीन मुहम्मद खाँ ने ही बेदखल कर दिया। उसने बंगाल और उडीसा को अपने नियन्त्रण में ले मुहम्मदशाह से अपने पद का अनुमोदन भी करा लिया। इसने भी मुगल दरबार से सम्बन्ध बनाकर रखा। इसे बंगाल की राजनीति की नई शक्तियों, अर्थात् जमींदारों, सौदागरों और बैंकरों का समर्थन प्राप्त था। 1739 ई० में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खाँ गवर्नर बना।

परन्तु 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खाँ ने विद्रोह कर सरफराज खाँ को घेरिया के स्थान पर हरा कर मार डाला। अलीवर्दी खाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गवर्नर बन गया। उसने सम्राट को 2 करोड़ रूपये नजराना देकर बादशाह की अनुमति ले ली। अलीवर्दी खाँ के काल में स्वायत्ता और बढ़ी। उसने मुगल शासक की परवाह न करते हुए अपने विश्वस्त व्यक्तियों को पटना, कटक और ढाका का उपनवाब नियुक्त किया। उसने राजस्व प्रशासन में बड़ी संख्या में हिन्दुओं को नियुक्त किया और एक मजबूत सैन्य शक्ति का निर्माण किया। अलीवर्दी खाँ के समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम हुई, जिसने दिल्ली दरबार से अपना सम्बन्ध कम कर लिया। इस प्रकार पूर्वी भारत में एक स्वतन्त्र राज्य का उदय हुआ।

हैदराबाद– हैदराबाद में आसफजाही वंश की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खाँ ने की। इसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की। फर्रूखसियर के समय इसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल दरबार की कठपुतली राजनीति के कारण उसने सैय्यद बन्धुओं को हटाने में मुहम्मद शाह की मदद की। मुहम्मद शाह ने 1722 में निजाम को वजीर नियुक्त किया। उसने दिल्ली में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन आपसी मतभेद के कारण निजाम 1724 में दक्षिण भारत आ गया। 1724 ई० में उसने हैदराबाद में दक्कन के सूबेदार मुबारिज को शकूरखेड़ा के युद्ध में हराकर स्वयं दक्कन का सूबेदार बन गया। सम्राट ने विवश होकर उसे दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और उसे आसफजाह की उपाधि भी दी।

निजामुल मुल्क ने मुगल सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति को बनाये रखते हुए हैदराबाद में राजनैतिक सुधार कार्य प्रारम्भ किये। उसने विद्रोही जमींदारों को वश में करने का प्रयास किया और हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई क्योंकि इनके हाथों में

आर्थिक शक्ति थी। हैदराबाद में जमीन से जुड़े बिचौलियों को प्रोत्साहित किया। ये राजनैतिक संतुलन स्थापित करने में बैंकरों, ऋणदाताओं और सैनिक अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि वे ही अनिवार्य वित्तीय और सैनिक सेवायें प्रदान करते थे।

इस समय मुगल सत्ता का नाम प्रतीकात्मक रूप से खुतवा में पढ़ा जाता था लेकिन व्यावहारिक दृष्टियों से निजाम स्वतन्त्र कामकाज करने लगा जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर, मनसब देना और महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना इत्यादि। 1748 ई० में आसफजहाँ की मृत्यु के बाद हैदराबाद को कई संकटों का सामना करना पड़ा। मराठों की लूटमार और हैदराबाद में गद्दी के लिए गृह युद्ध जिसमें फ्रांसीसियों, मराठो और बाद में अंग्रेजों के आ जाने से स्थिति खराब हो गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- एल० पी० शर्मा, आधुनिक भारत (1707–1967 A.D.) पृ० 22 से 29 संस्करण 2018, प्रकाशन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
- बी० एल० ग्रोवर, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृ० 6,7 एस० चन्द एंड कम्पनी प्रा० लि० रामनगर नई दिल्ली 2008